

Weekly One Liners 3rd to 9th of February 2025**Union Budget 2025: एक व्यापक योजना सूची**

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), उद्योग और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नई सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई। ये पहल ग्रामीण विकास, आर्थिक वृद्धि और विभिन्न वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। सरकार ने मौजूदा योजनाओं में भी बदलाव किए हैं, ताकि उनका प्रभाव और अधिक व्यापक हो सके। इन पहलों का मुख्य लक्ष्य किसानों, उद्यमियों, श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।

बजट 2025 में घोषित नई सरकारी योजनाएं**प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना**

उद्देश्य: कृषि उत्पादकता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।

लक्ष्य: 100 कम-उत्पादकता वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसान।

मुख्य विशेषताएँ:

- फसल विविधीकरण और सतत कृषि को प्रोत्साहन।
- सिंचाई सुविधाओं और भंडारण संरचना में सुधार।
- दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक आसान पहुंच।

ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम

उद्देश्य: ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।

लक्ष्य: युवा किसान, ग्रामीण महिलाएँ, सीमांत किसान और भूमिहीन परिवार।

मुख्य विशेषताएँ:

- कृषि, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास में निवेश।
- ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा।
- ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और व्यावसायिक अवसरों का सृजन।

आत्मनिर्भरता इन पल्सेस (दालों में आत्मनिर्भरता अभियान)

उद्देश्य: भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।

मुख्य विशेषताएँ:

- 6-वर्षीय मिशन, विशेष रूप से उड़द, तूर और मसूर दालों पर केंद्रित।
- NAFED और NCCF द्वारा पंजीकृत किसानों से दालों की खरीद।
- जलवायु सहनशील बीजों का विकास और प्रोटीन सामग्री में वृद्धि।

पहली बार उद्यमियों के लिए योजना

उद्देश्य: पहली बार व्यापार शुरू करने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को सहयोग देना।

मुख्य विशेषताएँ:

- 5 वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन की सुविधा।
- उद्यमिता कौशल के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना

उद्देश्य: बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता प्रदान करना।

लक्ष्य: 8 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ माताएँ और 20 लाख किशोरियाँ।

मुख्य विशेषताएँ:

- महत्वाकांक्षी जिलों में पोषण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि।
- पोषण स्तर सुधारने के लिए आंगनवाड़ियों को आधुनिक संसाधनों से लैस करना।

भारतीय भाषा पुस्तक योजना (Bharatiya Bhasha Pustak Scheme)

उद्देश्य: स्कूलों और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएँ:

- डिजिटल फॉर्मेट में क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएँगी, ताकि विषयों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

उद्देश्य: गिग (Gig) वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएँ:

- ई-श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स का पंजीकरण और आईडी कार्ड जारी किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत स्वास्थ्य कवरेज।

SWAMIH फंड 2

- उद्देश्य: मध्यम वर्गीय परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा करना।
- लक्ष्य: 1 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों के अधूरे घर पूरे करना।

मुख्य विशेषताएँ:

- ₹15,000 करोड़ का कोष, जो रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद करेगा।
- उन परिवारों पर विशेष ध्यान, जो घर के लिए ईएमआई और किराया दोनों चुका रहे हैं।

मौजूदा सरकारी योजनाओं में बदलाव**MSME की नई परिभाषा**

उद्देश्य: एमएसएमई (MSME) सेक्टर की तकनीकी क्षमताओं, विस्तार और पूंजी तक पहुंच को बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएँ:

- निवेश और कारोबार सीमा में संशोधन, जिससे अधिक व्यवसाय एमएसएमई के तहत आएंगे।
- संशोधित वर्गीकरण से छोटे और मध्यम उद्योगों को वृद्धि में मदद मिलेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

उद्देश्य: किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना।

मुख्य विशेषताएँ:

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।

क्रेडिट गारंटी फंड

उद्देश्य: MSME और स्टार्टअप के लिए ऋण पहुंच में सुधार।

मुख्य विशेषताएँ:

एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए उन्नत क्रेडिट गारंटी सुविधा।

- सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड।

स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स

उद्देश्य: नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना और उनके विस्तार में मदद करना।

मुख्य विशेषताएँ:

- ₹10,000 करोड़ के योगदान वाला नया फंड ऑफ फंड्स।
- स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता और दायरा बढ़ाया जाएगा।

अटल टिंकरिंग लैब्स (Atal Tinkering Labs)

उद्देश्य: युवाओं में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएँ:

- 5 वर्षों में 50,000 टिंकरिंग लैब्स सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएँगी।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi)

उद्देश्य: फुटपाथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएँ:

- बेहतर ऋण सुविधाएँ और UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
- फुटपाथ विक्रेताओं के लिए क्षमता-विकास (Capacity-Building) सहायता।

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)

उद्देश्य: ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएँ:

- मिशन का विस्तार कर 2028 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कवर किया जाएगा।
- ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष ध्यान।

उड़ान – क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN - Regional Connectivity Scheme)

उद्देश्य: देश के दूरस्थ और छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना।

मुख्य विशेषताएँ:

- संशोधित योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे हवाई अड्डों और हेलिपैड्स के विकास को बढ़ावा।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti)

उद्देश्य: डेटा और नक्शों के माध्यम से बुनियादी ढांचे की योजना को सुगम बनाना।

मुख्य विशेषताएँ:

- पीपीपी (PPP) और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जियोस्पेशियल डेटा की सुविधा।

पर्यटन में रोजगार-संचालित वृद्धि (Employment-Led Growth in Tourism)

उद्देश्य: पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना।

मुख्य विशेषताएँ:

- कौशल विकास कार्यक्रम और होमस्टे के लिए मुद्रा लोन।
- ई-वीजा सुविधाएँ और पर्यटन प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन।

प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप

उद्देश्य: तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएँ:

- IISc और IITs के लिए 10,000 शोध फेलोशिप दी जाएँगी।
- वित्तीय सहायता को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।

ग्रैमी पुरस्कार 2025: विजेताओं की पूरी सूची

लॉस एंजेलिस के Crypto.com एरेना में 2 फरवरी, 2025 को आयोजित 67वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स ने संगीत उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। कार्यक्रम के मेज़बान ट्रेवर नोहा ने इस आयोजन में अपनी शोमैनशिप और उत्साह से चार चांद लगाए, जिससे यह रात संगीत की विभिन्न शैलियों में कलाकारों की प्रतिभा का उत्सव बन गई। इस वर्ष बीयोंस ने इतिहास रचा, जबकि केंड्रिक लैमर ने कई पुरस्कार जीतकर अपने प्रभाव को और भी मजबूती से स्थापित किया।

2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में बीयोंस ने कैसे रचा इतिहास?

बीयोंस का 2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में जीतना बेहद ऐतिहासिक था। उन्होंने अपने पहले कंट्री एल्बम *Cowboy Carter* के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जिससे वह 26 वर्षों में यह सम्मान पाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई। इसके अलावा, बीयोंस ने बेस्ट कंट्री एल्बम और माइलि साइरस के साथ की गई *II MOST WANTED* के लिए बेस्ट कंट्री ड्युओ/ग्रुप परफॉर्मेंस का भी पुरस्कार जीता। उनकी विविध प्रतिभा संगीत उद्योग की सीमाओं को फिर से परिभाषित करती है।

2025 के ग्रैमी अवार्ड्स में केंड्रिक लैमर ने क्या हासिल किया?

केंड्रिक लैमर ने अपनी संगीत यात्रा में एक और प्रमुख उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने गीत *Not Like Us* के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्गा ऑफ द ईयर के पुरस्कार जीते, जो उनकी संगीत की दुनिया में एक सशक्त आवाज़ को दर्शाता है। लैमर की सफलता न केवल उनके संगीत की शैली और लिरिकल ब्रिलियंस को प्रमाणित करती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि उनका संगीत दुनिया भर में श्रोताओं के दिलों में गूँजता है।



2025 के ग्रैमी अवार्ड्स के नए चेहरे कौन थे?

इस रात में नए और उभरते कलाकारों ने भी अपनी जगह बनाई। चापल रोआन को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार मिला, जिन्होंने पिक पोनी क्लब की भावनात्मक परफॉर्मेंस दी और आने वाले कलाकारों के लिए स्थायी वेतन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उनका यह जीत यह दर्शाती है कि कैसे नए कलाकार संगीत उद्योग को अपनी अनोखी आवाज़ और दृष्टिकोण से आकार दे रहे हैं। इसके अलावा, सबरीना कारपेंटर ने भी अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, उन्होंने बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के पुरस्कार जीते।

ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में उन कलाकारों को कैसे सम्मानित किया गया जो अब हमारे बीच नहीं हैं?

ग्रैमी अवार्ड्स में उन कलाकारों को भी श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने अपने योगदान से संगीत और संस्कृति में अमिट छाप छोड़ी है। एक बहुत ही भावनात्मक पल तब आया जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह gesture अकादमी द्वारा उनके राष्ट्रपति पद के दौरान संगीत और संस्कृति में दिए गए योगदान को मान्यता देने का प्रतीक था।

2025 में प्रमुख ग्रैमी विजेताओं की पूरी सूची

Award Category	Winner(s)
Album of the Year	Beyoncé – “Cowboy Carter”
Record of the Year	Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Song of the Year	Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Best New Artist	Chappell Roan
Best Pop Solo Performance	Sabrina Carpenter – “Espresso”
Best Pop Vocal Album	Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”
Best Country Album	Beyoncé – “Cowboy Carter”
Best Country Duo/Group Performance	Beyoncé & Miley Cyrus – “II MOST WANTED”
Best Rap Album	J. Cole – “The Off-Season”
Best Rock Album	The Black Crowes – “Shake Your Money Maker”
Best R&B Song	Kehlani – “After Hours”
Best Dance/Electronic Performance	Justice & Tame Impala – “We Are the People”
Best Score Soundtrack	Bear McCreary – “God of War Ragnarök: Valhalla”
Dr. Dre Global Impact Award	Alicia Keys

केंद्र ने उच्च उत्पादकता के लिए नई कृषि-तकनीक योजनाओं का शुभारंभ किया

केंद्र सरकार ने कृषि प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादकता, सततता और किसानों की आय में सुधार करना है। ये पहलकदमियां डिजिटल प्रौद्योगिकियों, आधुनिक कृषि तकनीकों और संसाधन प्रबंधन की दक्षता को शामिल करती हैं, ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और पर्यावरणीय सततता को सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य सरकारी पहलकदमियां

- डिजिटल कृषि मिशन**
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा, और भू-स्थानिक तकनीकी का उपयोग:
 - फसल निगरानी में सुधार
 - मिट्टी प्रबंधन
 - मौसम पूर्वानुमान
- फसल सुधार और कृषि अनुसंधान**
 - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने पिछले दशक में 2,900 फसल किस्में विकसित की हैं।
 - 2,661 किस्में जैविक और अजैविक तनाव (रोग, कीड़े, सूखा आदि) के लिए प्रतिरोधक हैं।
 - उत्पादन और पशुपालन प्रसंस्करण के लिए 156 नई तकनीक/मशीनें पेश की गईं।
- पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में तकनीकी विकास**
 - उन्नत निदान, टीके और प्रसंस्करण विधियों का विकास।
 - पशु उत्पादकता, मत्स्य पालन की दक्षता और मछली स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार।
- किसानों को प्रशिक्षण और जागरूकता**
 - कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) और राज्य कृषि विश्वविद्यालय (SAUs) द्वारा:
 - किसानों के लिए प्रशिक्षण सत्र
 - खेतों में प्रदर्शन
 - खेत की दक्षता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
- कृषि विपणन और बाजार पहुंच**
 - e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) बेहतर मूल्य निर्धारण और पारदर्शिता के लिए।
 - किसान रेल और किसान उडान फसल उत्पादों के त्वरित परिवहन के लिए।
 - किसान उत्पादक संगठन (FPOs), जो बिचौलियों को कम करके किसानों के लाभ को बढ़ाते हैं।
 - कृषि-तकनीकी स्टार्टअप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे AGRI-Bazaar को बढ़ावा देना, ताकि किसानों और खरीदारों के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा मिले।
- सतत खेती और मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन**
 - मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देती है।
 - ICAR-सिफारिशित मिट्टी परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन:
 - रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी
 - मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार
 - माइक्रो-सीचाई और पानी की बचत के लिए "प्रति बूंद अधिक फसल" (PDMC) योजना।
- मूल्यवर्धन और कृषि प्रसंस्करण**
 - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पर ध्यान केंद्रित:
 - कृषि उत्पादों का मूल्य-वर्धित प्रसंस्करण
 - शैल्फ जीवन में वृद्धि
 - किसानों को कृषि उद्योगों से जोड़ना

केंद्रीय बजट 2025-26 परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को क्या मिलेगा?

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के रूप में परमाणु शक्ति को प्राथमिकता दी है और इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का आधार बनाया है। विकसित भारत (Viksit Bharat) परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत, भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह पहल जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन में घरेलू परमाणु क्षमताओं का विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) का अनुसंधान शामिल होगा।

केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा से जुड़ी प्रमुख घोषणाएँ

1. विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन

- सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर भारत को ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है।
- 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- इस मिशन के तहत नीतिगत सुधार, विधायी संशोधन और बुनियादी ढांचे में रणनीतिक निवेश किया जाएगा।

2. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) का अनुसंधान और विकास

- सरकार ने ₹20,000 करोड़ का बजट SMRs के अनुसंधान और निर्माण के लिए आवंटित किया है।
- 2033 तक पाँच स्वदेशी रूप से विकसित SMRs को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
- SMRs की उत्पादन क्षमता 30 MWe से 300+ MWe तक होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन संभव होगा और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी।
- यह तकनीक भूमि की कमी, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

3. निजी क्षेत्र की भागीदारी और विधायी सुधार

- सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम (Atomic Energy Act) और परमाणु क्षति हेतु सिविल दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act) में संशोधन करने जा रही है।
- निजी कंपनियों को "भारत स्मॉल रिएक्टर्स" (BSRs) के विकास में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- इन सुधारों से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

4. भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs) की स्थापना

- 220 MWe के प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स (PHWRs) विकसित किए जाएंगे, जो औद्योगिक क्षेत्रों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे।
- यह स्टील, एल्युमीनियम और धातु उद्योगों के लिए उपयुक्त होंगे।
- निजी कंपनियाँ भूमि, शीतलन जल (Cooling Water) और पूंजी निवेश प्रदान करेंगी, जबकि परमाणु ऊर्जा निगम (NPCIL) डिज़ाइन, गुणवत्ता नियंत्रण और संचालन की निगरानी करेगा।

5. अन्य उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों का विकास

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) नए प्रकार के परमाणु रिएक्टरों पर काम कर रहा है, जिनमें शामिल हैं:
 - हाई-टेम्परेचर गैस-कूल्ड रिएक्टर्स (HTGRs): हाइड्रोजन उत्पादन के लिए विकसित किए जा रहे हैं।
 - मोल्टन साल्ट रिएक्टर्स (MSRs): थोरियम पर आधारित हैं और भारत के समृद्ध थोरियम संसाधनों का उपयोग करने में सहायक होंगे।
- ये उन्नत रिएक्टर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में योगदान देने के लिए आवश्यक हैं।

6. परमाणु क्षमता का विस्तार

- भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,180 MW से बढ़ाकर 22,480 MW करने की योजना बनाई गई है, जिसे 2031-32 तक पूरा किया जाएगा।
- गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 10 नए रिएक्टर (8,000 MW क्षमता) स्थापित किए जाएंगे।
- आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा (Kovvada) प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका के सहयोग से 1,208 MW के छह रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे।

7. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हाल की उपलब्धियाँ

- 19 सितंबर, 2024 को राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP-7) की यूनिट-7 ने क्रिटिकलिटी प्राप्त की, जो स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- झाड़गुडा खदानों (Jaduguda Mines) में नए यूरेनियम भंडार की खोज हुई है, जिससे यह संसाधन अगले 50 वर्षों तक उपलब्ध रहेगा।
- काकरापार (गुजरात) में 700 MWe PHWR रिएक्टर की पहली दो इकाइयों वाणिज्यिक रूप से चालू हो चुकी हैं।

8. सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता

- भारत के परमाणु संयंत्र कड़े सुरक्षा मानकों और अंतरराष्ट्रीय निगरानी के तहत संचालित होते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।
- सरकार का लक्ष्य "नेट-जीरो" उत्सर्जन प्राप्त करना और स्वच्छ, सुरक्षित और स्थायी ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है।

ओडिशा ने BBBP योजना के अंतर्गत प्रमुख पहलों को लागू किया

भारत में लिंग असमानता और घटते बाल लिंगानुपात को सुधारने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना शुरू की गई थी। इस योजना के उद्देश्यों को साकार करने के लिए ओडिशा सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जो किशोरियों को सशक्त बनाने, बाल विवाह रोकने और शिक्षा एवं आत्मरक्षा कौशल को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। ये पहल विभिन्न जिलों में लागू की गई हैं और इनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण तैयार किया जा सके।

ओडिशा में BBBP की प्रमुख पहलें

'निर्भया कढ़ी' (निडर कली) और 'मो गेल्हा जिया' (मेरी प्रिय बेटी) – गंजाम जिला

उद्देश्य:

- किशोरियों को सशक्त बनाना और लिंग समानता को बढ़ावा देना।
- बाल विवाह, भ्रूण हत्या और लिंग चयन को रोकना।

प्रभाव क्षेत्र:

- गंजाम जिले के 3,309 गांवों में 1,83,933 किशोरियों को शामिल किया गया।

मुख्य उपलब्धियां:

- गंजाम को 3 जनवरी 2022 को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया।
- 2019-2024 के बीच 953 में से 20 बाल विवाह रोके गए।
- 3,614 स्कूलों के 4,50,000 छात्रों ने 'बाल विवाह को ना' कहने की शपथ ली।
- बाल विवाह की पहली सूचना देने वाले को ₹5,000 का इनाम।
- ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (OSCPDR) ने गंजाम के प्रयासों को मान्यता दी।

'कल्पना अभियान' - ढेंकानाल जिला

उद्देश्य:

- 10-19 वर्ष की किशोरियों की निगरानी और ट्रैकिंग।
- बाल विवाह रोकने के लिए समुदाय की भागीदारी को मजबूत करना।

प्रभाव क्षेत्र:

- 1,13,515 किशोरियों की पहचान कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल किया गया।

मुख्य उपलब्धियां:

- 2019-2024 के बीच 343 बाल विवाह रोके गए।
- 3,425 स्कूलों के 4,45,000 छात्रों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली।
- 1,211 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- ढेंकानाल प्रशासन को 'अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह 2024' के दौरान सम्मानित किया गया।
- ओडिशा महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) और मिशन शक्ति ने पहल को मान्यता दी।
- बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने पर वर्षा प्रियदर्शिनी साहू को सम्मानित किया गया।
- एक बच्चाई गई पर्वतारोही को 'कल्पना अभियान' का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया।

'स्वर्णा कालिका' - क्योझर जिला

उद्देश्य:

- बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- समुदाय-आधारित हस्तक्षेप को बढ़ावा देना।

मुख्य उपलब्धियां:

- 2024 तक बाल विवाह में 50% की कमी दर्ज की गई।
- 2,000 हितधारकों को जागरूकता अभियानों में शामिल किया गया।
- ADVIKA ऐप को निगरानी और हस्तक्षेप के लिए बढ़ावा दिया गया।
- समुदाय के नेताओं और किशोरियों ने सक्रिय रूप से अभियान में भाग लिया।

'वीरांगना योजना' - देवगढ़ जिला

उद्देश्य:

- किशोरियों को मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना।
- आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना।

प्रभाव क्षेत्र:

- 500 किशोरियों को 30-दिवसीय मार्शल आर्ट शिविर में प्रशिक्षित किया गया।
- 300 शिक्षकों और अभिभावकों को लड़कियों के कानूनी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया गया।

मुख्य उपलब्धियां:

- 50 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए, जिन्होंने 300 स्कूलों में 6,000 छात्राओं को प्रशिक्षित किया।
- इस पहल को स्कूलों और कॉलेजों में संस्थागत रूप से लागू किया गया।
- यह योजना जिला महोत्सवों में प्रदर्शित की गई और प्रतिष्ठित 'SKOCH अवार्ड' जीता।

निष्कर्ष:

ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई ये पहलें बालिकाओं के संरक्षण, सशक्तिकरण और शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रभावी कदम हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने, बाल विवाह को रोकने और उनके उज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

आरबीआई मौद्रिक नीति समिति 2025: मुख्य बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 5 से 7 फरवरी 2025 तक अपनी 53वीं बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता RBI के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की। इस बैठक में डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव ने भाग लिया।

वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के आर्थिक रुझानों का मूल्यांकन करने के बाद, MPC ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट (bps) की कटौती करने और तटस्थ मौद्रिक नीति रुख (Neutral Monetary Policy Stance) बनाए रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय मुद्रास्फीति (Inflation) नियंत्रण, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को संतुलित रखने की RBI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

RBI मौद्रिक नीति समिति 2025 की प्रमुख घोषणाएँ

1. रेपो दर में कटौती

- रेपो दर को 25 आधार अंक (bps) घटाकर 6.25% कर दिया गया है।
- इसका उद्देश्य उधारी को सस्ता बनाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

BANK MAHAPACK PLUS
For IBPS, SBI, SIDBI, RBI
Grade B, +5 More
Selection Ka Saathi

2. अन्य प्रमुख दरों में बदलाव

रेपो दर में कटौती के बाद, RBI ने अन्य महत्वपूर्ण दरों को भी समायोजित किया:

दर	नई दर (%)
स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर	6.00%
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर	6.50%
बैंक दर	6.50%

3. तटस्थ मौद्रिक नीति रुख

RBI ने तटस्थ रुख बनाए रखा है, जिससे भविष्य में किसी भी आर्थिक अस्थिरता के अनुसार नीतियों को समायोजित किया जा सके।

4. मुद्रास्फीति लक्ष्य और आर्थिक वृद्धि

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को **4% (+/- 2%)** के दायरे में बनाए रखने का लक्ष्य।
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि को संतुलित रूप से बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित।

आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति का आउटलुक

1. वैश्विक आर्थिक रुझान

वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि औसत से कम बनी हुई है, जिससे भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। प्रमुख चुनौतियाँ:

- अस्थिर वैश्विक मुद्रास्फीति
- भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions)
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों में अनिश्चितता
- अमेरिकी डॉलर की मजबूती से वित्तीय बाजारों में अस्थिरता

2. भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर **6.4%** रहने का अनुमान।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर **6.7%** रहने की संभावना।

त्रैमासिक GDP वृद्धि दर पूर्वानुमान (2025-26)

तिमाही	GDP वृद्धि दर (%)
Q1 (अप्रैल-जून 2025)	6.7%
Q2 (जुलाई-सितंबर 2025)	7.0%
Q3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)	6.5%
Q4 (जनवरी-मार्च 2026)	6.5%

संभावित आर्थिक जोखिम

- भू-राजनीतिक अस्थिरता (जैसे रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व तनाव)।
- व्यापार नीतियों में संरक्षणवाद (टैरिफ और निर्यात प्रतिबंध)।
- अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव।
- वित्तीय बाजारों में अस्थिरता।

3. मुद्रास्फीति रुझान

- अक्टूबर 2024 में **6.2%** के उच्चतम स्तर पर पहुँचने के बाद, नवंबर-दिसंबर 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट आई।
- इस गिरावट के कारण:
 - सब्जियों की कीमतों में कमी
 - कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) स्थिर
 - ईंधन क्षेत्र में मूल्य गिरावट

त्रैमासिक CPI मुद्रास्फीति पूर्वानुमान (2025-26)

तिमाही	CPI मुद्रास्फीति (%)
Q1 (अप्रैल-जून 2025)	4.5%
Q2 (जुलाई-सितंबर 2025)	4.0%
Q3 (अक्टूबर-दिसंबर 2025)	3.8%
Q4 (जनवरी-मार्च 2026)	4.2%

- सामान्य मानसून और अच्छी रबी फसल उत्पादन से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने की उम्मीद।
- हालाँकि, वैश्विक अस्थिरता और ऊर्जा मूल्य अस्थिरता संभावित जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

मौद्रिक नीति निर्णयों का औचित्य

1. मुद्रास्फीति में कमी से दर कटौती का समर्थन

- MPC ने मुद्रास्फीति में निरंतर गिरावट को देखते हुए नीतिगत दर कटौती की सिफारिश की।
- खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट और पूर्व नीतिगत उपायों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया।

2. आर्थिक विकास को समर्थन आवश्यक

- वर्तमान आर्थिक विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में कम है।
- रेपो दर में कटौती से:
 - ऋण लेना और निवेश करना आसान होगा।
 - निजी खपत को बढ़ावा मिलेगा।
 - अर्थव्यवस्था की रिकवरी तेज होगी।

3. वैश्विक अनिश्चितताओं के प्रति सतर्कता

- अस्थिर वित्तीय बाजार और व्यापारिक नीतियों में बदलाव के कारण RBI सतर्क रहेगा।
- मौसमी घटनाओं का भी कृषि उत्पादन और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ सकता है।

4. लचीलेपन के लिए तटस्थ नीति रुख

- अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार भविष्य में नीतिगत समायोजन की संभावना बनी रहेगी।

आगामी MPC बैठकें

- MPC बैठक के मिनट्स का प्रकाशन - 21 फरवरी 2025।
- अगली MPC बैठक - 7 से 9 अप्रैल 2025।

RBI भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों की बारीकी से निगरानी करेगा और आवश्यकतानुसार मौद्रिक नीति में समायोजन करेगा।

कैबिनेट ने नया आयकर विधेयक 2025 पारित किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक (Income Tax Bill) को मंजूरी दे दी है, जो 1961 के छह दशक पुराने आयकर अधिनियम (Income Tax Act, 1961) की जगह लेगा। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल, आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है, जिससे करदाताओं के लिए इसे समझना और अनुपालन करना आसान हो जाए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में घोषणा की कि नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा। संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद, इसे वित्त स्थायी समिति (Standing Committee on Finance) के पास आगे की समीक्षा और चर्चा के लिए भेजा जाएगा।

नए आयकर विधेयक की आवश्यकता क्यों पड़ी?

1961 का आयकर अधिनियम कई बार संशोधित किया जा चुका है, जिससे यह जटिल और करदाताओं के लिए कठिन हो गया है। सरकार ने इसकी जटिलताओं को दूर करने के लिए नया कानून लाने का निर्णय लिया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

- कानूनी भाषा को सरल बनाना, जिससे करदाताओं के लिए इसे समझना आसान हो।
- विवादों और मुकदमों को कम करना, ताकि कर व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता और निश्चितता हो।
- व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कर नियमों को स्पष्ट करना, जिससे करदाता अनावश्यक भ्रम से बच सकें।
- पुरानी और अप्रासंगिक धाराओं को हटाना, जिससे कर ढांचा आधुनिक बन सके।

सरकार का मानना है कि एक स्पष्ट और संक्षिप्त कर संरचना से कर अनुपालन (tax compliance) में वृद्धि होगी और कर चोरी (tax evasion) को रोका जा सकेगा।

नए आयकर विधेयक की मुख्य विशेषताएं

सरल और प्रभावी कर प्रणाली बनाने के लिए, इस नए प्रत्यक्ष कर विधेयक (Direct Tax Bill) को उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया जा रहा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

कोई अतिरिक्त कर बोझ नहीं

नया विधेयक कर कानूनों को सरल बनाएगा, लेकिन इसमें नए करों को शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना है, न कि कर दरों को बढ़ाना।

सरल भाषा और संरचना

1961 के आयकर अधिनियम में जटिल कानूनी शब्दावली और लंबी व्याख्याएं शामिल थीं, जिससे आम करदाता के लिए इसे समझना मुश्किल था।

नया विधेयक स्पष्ट और संक्षिप्त होगा, जिससे बिना विशेषज्ञ की मदद के भी करदाता इसे आसानी से समझ सकें।

कर विवादों में कमी

- मौजूदा कर प्रणाली में कानूनी मुकदमों और कर विवादों की संख्या अधिक है।
- स्पष्ट कर प्रावधानों के माध्यम से विवादों को कम करेगा।
- विवाद समाधान तंत्र (Dispute Resolution Mechanism) लागू करेगा, जिससे कर मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके।
- व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कर अनुपालन को सरल बनाएगा।

अनुपालन में कमी (Compliance Reduction)

- सरकार ने करदाताओं की अनुपालन संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। इस दिशा में उठाए गए कदम:
- अनावश्यक दस्तावेजी आवश्यकताओं को समाप्त करना।
- कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
- व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए कर प्रपत्रों (tax forms) की संख्या को कम करना।

सार्वजनिक परामर्श और हितधारकों के सुझाव

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा के लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए थे। चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

- कानूनी भाषा को सरल बनाना।
- कर विवादों में कमी लाना।
- अनुपालन बोझ को कम करना।
- अप्रचलित प्रावधानों को हटाना।

सरकार को करदाताओं, व्यवसायों और उद्योग विशेषज्ञों से 6,500 से अधिक सुझाव मिले। इससे सरकार का पारदर्शी और भागीदारी आधारित दृष्टिकोण सामने आया।

नए आयकर विधेयक को लागू करने की प्रक्रिया

कैबिनेट से मंजूरी और संसद में प्रस्तुति

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है, और इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।

वित्त स्थायी समिति की समीक्षा

- विधेयक को संसद में पेश किए जाने के बाद, इसे वित्त स्थायी समिति (Standing Committee on Finance) को भेजा जाएगा।
- समिति इस विधेयक की विस्तार से समीक्षा करेगी, हितधारकों की प्रतिक्रिया लेगी और आवश्यक संशोधन सुझाएगी।

अंतिम मंजूरी और कार्यान्वयन

- चर्चा के बाद, विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कराया जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा।

नए आयकर विधेयक के प्रभाव

- बेहतर स्पष्टता और पारदर्शिता – सरल भाषा और स्पष्ट प्रावधानों से करदाताओं को इसे समझने में आसानी होगी।
- कर विवादों में कमी – स्पष्ट कर कानूनों से मुकदमेबाजी और कर विवाद कम होंगे।
- आसान अनुपालन – व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए कर फाइलिंग की प्रक्रिया कम जटिल होगी।
- निवेश को बढ़ावा – स्थिर और पारदर्शी कर प्रणाली से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा।



National Affairs

- भारत में रेलवे सुरक्षा में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें कावच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) सिस्टम का देशभर में विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना अगले छह वर्षों में पूरी भारतीय रेलवे नेटवर्क को कवर करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है – सुरक्षित और अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना, साथ ही दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक पर यात्री विश्वास को बढ़ाना। [\(Click here to read article\)](#)
- भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग (Election Commission of India) को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया है, जो पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया की निगरानी और संचालन के लिए जिम्मेदार है। यह आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में पहला चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को गठित किया गया था। [\(Click here to read article\)](#)
- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। यह पहल वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर क्योंकि रीवा ऐतिहासिक रूप से अंतिम ज्ञात जंगली सफेद बाघ से जुड़ा हुआ है। इस परियोजना को 2011 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी, और इसे गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा, जो मुकुंदपुर के सफेद बाघ सफारी के पास स्थित है। इस प्रजनन केंद्र से जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा, वन्यजीव पर्यटन का विकास और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। [\(Click here to read article\)](#)
- महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो AI शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। यह विश्वविद्यालय AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने, कौशल विकास का समर्थन करने और AI नीतियों को आकार देने का कार्य करेगा, जिससे महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर AI शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन सके। [\(Click here to read article\)](#)
- केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा के रूप में परमाणु शक्ति को प्राथमिकता दी है और इसे दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का आधार बनाया है। विकसित भारत (Viksit Bharat) परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत, भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह पहल जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuels) पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन में घरेलू परमाणु क्षमताओं का विकास, निजी क्षेत्र की भागीदारी और उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) का अनुसंधान शामिल होगा। [\(Click here to read article\)](#)

- आयुष मंत्रालय ने “शतावरी – बेहतर स्वास्थ्य के लिए” नामक प्रजाति-विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शतावरी के औषधीय लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस पहल का उद्घाटन श्री प्रतापराव जाधव, (स्वतंत्र प्रभार) आयुष राज्य मंत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर वैद्य राजेश कोटेचा (सचिव, आयुष मंत्रालय) और डॉ. महेश कुमार दधीच (सीईओ, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड – NMPB) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह अभियान आंवला, मोरिंगा, गिलोय और अश्वगंधा जैसी औषधीय पौधों को बढ़ावा देने वाली पूर्व की पहलों की सफलता के बाद शुरू किया गया है। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी पहलों के माध्यम से अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में 38वें स्थान पर काबिज भारत का लक्ष्य 2030 तक शीर्ष 25 देशों में स्थान बनाना है। बढ़ते बुनियादी ढांचे, नीति-संचालित सुधारों और मल्टी-मोडल परिवहन की मदद से, यह क्षेत्र 2029 तक \$484.43 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर सिंगल डिजिट में लाना है। [\(Click here to read article\)](#)
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए आयकर विधेयक (Income Tax Bill) को मंजूरी दे दी है, जो 1961 के छह दशक पुराने आयकर अधिनियम (Income Tax Act, 1961) की जगह लेगा। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल, आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाना है, जिससे करदाताओं के लिए इसे समझना और अनुपालन करना आसान हो जाए। [\(Click here to read article\)](#)
- नीति आयोग ने 6 फरवरी 2025 को “विकसित भारत @ 2047: अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और विधि को सशक्त बनाना” शीर्षक से एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया गया, जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और सीईओ के साथ-साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और रक्षा मंत्रालय के सचिव सहित कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की 75वीं वर्षगांठ विज्ञान भवन, नई दिल्ली में धूमधाम से मनाई। यह कार्यक्रम साध्य-आधारित नीति निर्माण, डेटा-आधारित प्रशासन और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों को जोड़ने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। [\(Click here to read article\)](#)

States in the News

- आंध्र प्रदेश सरकार ने 'मना मित्र' (Mana Mitra) नामक एक अनोखी व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से नागरिक अब 161 सरकारी सेवाओं तक व्हाट्सएप के जरिए आसानी से पहुंच सकेंगे। यह सेवा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार और रियल-टाइम गवर्नेंस (RTG) मंत्री नारा लोकेश द्वारा अमरावती में लॉन्च की गई। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के और करीब लाना है। यह सेवा मेटा (Meta) के सहयोग से विकसित की गई है और इसे भविष्य में ब्लॉकचेन और एआई (AI) तकनीक के साथ और उन्नत किया जाएगा। [\(Click here to read article\)](#)

International Affairs

- गुजरात सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है। इस पैनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा की जा रही है और इसे 45 दिनों के भीतर यूसीसी के संभावित कार्यान्वयन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है। इस समिति का गठन सरकार के सभी नागरिकों को समान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण भारत में समान कानून लागू करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। [\(Click here to read article\)](#)
- हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अवाडा ग्रुप (Avaada Group) ने कासाले (Casale) के साथ साझेदारी कर गोपालपुर, ओडिशा में 1,500 टन प्रति दिन (TPD) की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अत्याधुनिक अमोनिया उत्पादन तकनीक का उपयोग करके शून्य-कार्बन प्रक्रिया विकसित करना है। यह परियोजना न केवल भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, बल्कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अवाडा की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए 'चंद्रयान से चुनाव तक' नामक एक अनूठी और भविष्यवादी पहल शुरू की है। पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी में एक विशेष मतदान केंद्र को अंतरिक्ष-थीम आधारित अनुभव में बदल दिया गया है, जो भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों से प्रेरित है। यह पहल न केवल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का उत्सव मनाती है, बल्कि युवा और बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। [\(Click here to read article\)](#)
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ती मांग और वैश्विक स्तर पर भांग (केनबिस) की औषधीय, कृषि और औद्योगिक उपयोगिता को मान्यता देते हुए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह परियोजना राज्य में भांग की खेती की संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी, विशेष रूप से इसके औषधीय और औद्योगिक उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। [\(Click here to read article\)](#)
- BIMSTEC युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में 7 से 11 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। यह सम्मेलन BIMSTEC देशों के युवा नेताओं को एक मंच पर लाकर सहयोग, नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 8 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के युवाओं के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना है। इसे भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य फोकस युवा-नेतृत्व वाली पहलों, नेतृत्व चर्चाओं और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर रहेगा। [\(Click here to read article\)](#)
- दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के रिजल्ट शनिवार (08 फरवरी 2025) को आए। भाजपा ने 26 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी (AAP) ने 22 सीटें जीतीं। भाजपा+ को AAP से 3.6% ज्यादा वोट मिले। इससे 26 सीटें ज्यादा मिलीं। पिछली चुनाव में 8 सीटें थीं। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। [\(Click here to read article\)](#)

- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो (DRC) में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय दूतावास ने बुकावु शहर में रह रहे भारतीयों को तुरंत वहां से निकलने की सलाह दी है। यह चेतावनी पूर्वी डीआरसी में विद्रोही समूहों, विशेष रूप से एम23 (M23) समूह, की बढ़ती गतिविधियों के कारण जारी की गई है, जिन्होंने पहले ही गोमा जैसे आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। यह सलाह भारतीय दूतावास की अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। [\(Click here to read article\)](#)
- 30 जनवरी 2025 को, न्यूज़ीलैंड की संसद में एक ऐतिहासिक क्षण घटित हुआ जब देश ने एक ऐसा कानून पारित किया, जिसके तहत माउंट तरानाकी, जिसे तारा नाकी माउंगा भी कहा जाता है, को कानूनी व्यक्तित्व (लिंगल पर्सनहुड) दिया गया। यह अभूतपूर्व निर्णय पर्वत को एक जीवित प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान करता है, जिसमें मानव के समान अधिकार होते हैं। यह कदम Māori लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से गहरे जुड़े हुए हैं और इसका उद्देश्य पिछले अन्यायों को ठीक करना और पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देना है। [\(Click here to read article\)](#)
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को, एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मेक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर भारी शुल्क लागू किया गया। यह कदम अवैध आप्रवासन और फेंटेनिल तस्करी जैसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से था, लेकिन इसने प्रभावित देशों से कड़ी प्रत्युत्तर कार्रवाई को जन्म दिया। इस निर्णय ने वैश्विक आर्थिक बहस को जन्म दिया, जिसमें विश्लेषकों ने मुद्रास्फीति के जोखिम, धीमी आर्थिक वृद्धि और संभावित व्यापार युद्धों के बारे में चेतावनी दी। [\(Click here to read article\)](#)
- श्रीलंका में 65 वर्षों में सबसे अधिक मुद्रा स्फीति (डिफ्लेशन) दर्ज की गई, जहां जनवरी 2025 में उपभोक्ता मूल्य 4.0% गिर गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह लगातार पांचवां महीना है जब देश में डिफ्लेशन देखा गया है, जो देश की सबसे खराब वित्तीय संकट के बाद उसके आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। यह रिकॉर्ड डिफ्लेशन मुख्य रूप से बिजली और ईंधन की कीमतों में तेज गिरावट के कारण हुआ है। श्रीलंका में मुद्रास्फीति, जो सितंबर 2022 में 69.8% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, अब तेजी से कम हो रही है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व में श्रीलंकाई सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आईएमएफ समर्थित आर्थिक सुधारों को लागू कर रही है। [\(Click here to read article\)](#)
- डेनमार्क के दक्षिणपंथी राजनेता रासमस पलुडन ने 1 फरवरी, 2025 को, कोपेनहेगन में तुर्की दूतावास के बाहर एक पवित्र कुरान को आग लगा दी, जिससे यह घटना तेजी से वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है। यह घटना एक वायरल वीडियो के रूप में रिकॉर्ड की गई और व्यापक रूप से साझा की गई, जिसने यूरोप में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, धार्मिक संवेदनाओं और नफरत भरे भाषण पर गरमागरम बहस को फिर से जगाया। पलुडन, जो दाएं पक्षी दल "स्ट्राम कुर्स" (हार्ड लाइन) के संस्थापक हैं, ने दावा किया कि वह यह कुरान जलाने का कार्य इराकी शरणार्थी सल्वान मोमिका को श्रद्धांजलि अर्पित करने के रूप में कर रहे थे, जो कुछ दिन पहले मारे गए थे। [\(Click here to read article\)](#)

- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विदेशी खर्च के कट्टर आलोचक रहे हैं, उनका तर्क है कि यह अमेरिकी करदाताओं के लिए लाभदायक नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) को निशाना बनाया है, इसे “कट्टरपंथी पागलों” द्वारा संचालित संगठन बताया। ([Click here to read article](#))
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के विभिन्न निकायों में अमेरिकी भागीदारी पर पड़ा, जिसमें यू.एन. मानवाधिकार परिषद और यूएनआरडब्ल्यूए (पैलेस्टीनियों को मानवीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी) शामिल हैं। इस कदम में यू.एन. और इसके संबंधित संगठनों के लिए अमेरिकी वित्तीय योगदान की समीक्षा करने की बात भी की गई। ट्रंप का इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पीछे हटने और अमेरिकी वित्तीय योगदान की समीक्षा करने का निर्णय उनके प्रशासन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर निरंतर आलोचना का हिस्सा था, विशेष रूप से वैश्विक संघर्षों के समाधान में। ([Click here to read article](#))
- GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड (GAL) ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट (UNGC) में शामिल होकर अपने सतत विकास और जिम्मेदार व्यापार प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। इस साझेदारी के माध्यम से GAL ने UNGC के दस सिद्धांतों जैसे मानव अधिकारों, श्रम मानकों, पर्यावरण संरक्षण और भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के साथ अपने संचालन को संरेखित करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही GAL यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह वैश्विक सततता एजेंडे में योगदान दे सके। ([Click here to read article](#))
- अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर निकलने की घोषणा की है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इसी तरह के फैसले के बाद हुआ है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सरकार ने WHO की स्वास्थ्य नीतियों, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर गहरी असहमति जताई है। इस निर्णय ने अर्जेंटीना की वैश्विक स्थिति, स्वास्थ्य नीति और WHO की विश्वसनीयता पर प्रभाव को लेकर बहस छेड़ दी है। आलोचकों का कहना है कि यह फैसला कांग्रेस की मंजूरी के बिना पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता और इससे अर्जेंटीना की स्वास्थ्य प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। ([Click here to read article](#))
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 5 फरवरी 2025 को “नो मेन इन विमेंस स्पोर्ट्स एक्जीक्यूटिव ऑर्डर” पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित करता है। यह ट्रंप प्रशासन का 20 जनवरी 2025 को कार्यभार संभालने के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ चौथा कार्यकारी आदेश है। ([Click here to read article](#))
- पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन (SUPARCO) ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (CNSA) के साथ चांग’ए-8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है, जो 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह पहली बार है जब पाकिस्तान किसी चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है, जो देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मिशन के तहत, चीन के अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन (ILRS) परियोजना के हिस्से के रूप में पाकिस्तान का स्वदेशी रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा। ([Click here to read article](#))
- वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार किए हैं। यह उपलब्धि संकटग्रस्त मार्सुपियल (थैलीधारी) प्रजातियों के संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और विलुप्ति के खतरे से बचाने में सहायक हो सकती है। ([Click here to read article](#))
- चीन का AI चैटबॉट DeepSeek AI हाल ही में वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इसे शुरू में चीन के ChatGPT के जवाब के रूप में देखा गया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह विभिन्न देशों के सरकारी नियामकों की कड़ी जांच के दायरे में आ गया। डीपसीक पर बैन लगाने वालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत और अन्य देश शामिल हैं। ([Click here to read article](#))
- पनामा ने आधिकारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से बाहर होने की घोषणा की है, जो एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक बदलाव को दर्शाता है। राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनो के इस फैसले से अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव साफ नजर आते हैं, खासकर पनामा नहर को लेकर। यह कदम पनामा की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसमें अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना और देश में चीनी निवेश की समीक्षा करना शामिल है। ([Click here to read article](#))

Agreements/MoUs Signed

- भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान (IICA) और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 4 फरवरी 2025 को IICA-CMAI मास्टरक्लास ऑन ग्लोबल एंड इंडियन कार्बन मार्केट्स के उद्घाटन सत्र के दौरान घोषित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और सतत ऊर्जा समाधानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो भारत के आर्थिक और पर्यावरणीय भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे। ([Click here to read article](#))

Banking/Economy/Business News

- भारत में क्रिप्टोकॉरेसी क्षेत्र को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने Bybit Fintech Limited पर ₹9.27 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के उल्लंघन के चलते लगाया गया, क्योंकि Bybit ने भारत में उचित पंजीकरण के बिना अपने परिचालन का विस्तार किया। इसके अलावा, FIU-IND ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत Bybit की वेबसाइटों को भी ब्लॉक कर दिया, जिससे सरकार की सख्त नियामक नीति स्पष्ट होती है। ([Click here to read article](#))
- फूड और डिलीवरी दिग्गज Zomato ने एक बड़े कॉर्पोरेट रीब्रांडिंग की घोषणा की है, जिसके तहत कंपनी का नाम बदलकर “Eternal” कर दिया गया है। यह बदलाव 6 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। यह रीब्रांडिंग कंपनी के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, जिसमें इसके विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों को एक ही छत्रछाया में लाया जाएगा। ([Click here to read article](#))

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सुधार किए गए हैं। वित्तीय क्षेत्र में किए गए बदलावों में बीमा, पेंशन, द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs), KYC प्रक्रिया में सरलीकरण और कंपनियों के विलय को आसान बनाने जैसे सुधार शामिल हैं। [\(Click here to read article\)](#)
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), उद्योग और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नई सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई। ये पहल ग्रामीण विकास, आर्थिक वृद्धि और विभिन्न वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। सरकार ने मौजूदा योजनाओं में भी बदलाव किए हैं, ताकि उनका प्रभाव और अधिक व्यापक हो सके। इन पहलों का मुख्य लक्ष्य किसानों, उद्यमियों, श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। [\(Click here to read article\)](#)
- केंद्रीय बजट 2025-26, जिसे 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, में लैंगिक बजट (Gender Budgeting) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। इस बार कुल केंद्रीय बजट का 8.86% हिस्सा महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के 6.8% की तुलना में अधिक है। महिलाओं के लिए ₹4.49 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹3.27 लाख करोड़ की तुलना में 37.25% की वृद्धि को दर्शाता है। [\(Click here to read article\)](#)
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने भारत में महिला श्रम भागीदारी दर (FLFPR) में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण हुआ। यह वृद्धि देश के समग्र श्रम बाजार संकेतकों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानी जा रही है। 31 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत इस सर्वेक्षण में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने में सरकार की विभिन्न योजनाओं और महिला उद्यमिता पहलों की भूमिका को प्रमुख रूप से दर्शाया गया। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत की अर्थव्यवस्था का FY26 में 6.5% वृद्धि दर रहने का अनुमान है, जो कि FY25 में अनुमानित 6.4% से थोड़ा अधिक है। क्रिसिल की रिपोर्ट में कई ऐसे कारकों का उल्लेख किया गया है, जो इस वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे, जिनमें कम महंगाई, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा दरों में कमी की संभावना, और सामान्य मानसून और स्थिर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ शामिल हैं। हालांकि, रिपोर्ट में कुछ संभावित चुनौतियाँ भी रेखांकित की गई हैं, जिनमें वैश्विक व्यापार बाधाएँ, कमजोर निर्यात प्रदर्शन, और मजबूत निजी क्षेत्र निवेश की आवश्यकता शामिल है। [\(Click here to read article\)](#)
- रेपो दर और रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये दरें वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधारी की लागत को प्रभावित करती हैं, जो बदले में ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और समग्र आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करती हैं। इन दरों में बदलाव के माध्यम से, RBI तरलता को नियंत्रित कर सकता है और

वित्तीय प्रणाली में फंड के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, जिससे ये भारत की मौद्रिक नीति ढांचे के प्रमुख तत्व बन जाते हैं। [\(Click here to read article\)](#)

- इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस ने एक महत्वपूर्ण बैंकश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य लाखों भारतीयों के लिए जीवन बीमा को अधिक सुलभ बनाना है। यह सहयोग IPPB के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करेगा ताकि पीएनबी मेटलाइफ के बीमा समाधान, विशेष रूप से दूरस्थ और अविकसित क्षेत्रों में, लोगों तक पहुंच सकें। दोनों संस्थान मिलकर वित्तीय सुरक्षा की खाई को पाटने और अधिक व्यापक ग्राहक आधार को किफायती जीवन बीमा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। [\(Click here to read article\)](#)
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान की पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। RBI ने अपने नियामक सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox) के तहत ऑफलाइन भुगतान समाधान का परीक्षण करने के लिए एक्सटो इंडिया टेक्नोलॉजीज (Exto India Technologies) को चुना है। यह पहल उन क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को समर्थन देने के लिए बनाई गई है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित या बिल्कुल नहीं है, जिससे सभी के लिए एक समावेशी भुगतान प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। [\(Click here to read article\)](#)
- एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग (CCL) 2025 के लिए कर्नाटक बुलडोजर्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जो 8 फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है। इस सहयोग के तहत एयरटेल पेमेंट्स बैंक टीम का सह-प्रायोजक (co-sponsor) बनेगा और भारत भर के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखेगा। यह पहल बैंक की डिजिटल सुरक्षा और वित्तीय जागरूकता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जो क्रिकेट जैसे लोकप्रिय मंच के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में सहायक होगी। [\(Click here to read article\)](#)
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) पंजीकृत बाजार मध्यस्थों के लिए एक सुरक्षित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) तंत्र पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य निवेशक सुरक्षा को बढ़ाना, धोखाधड़ी लेनदेन को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि भुगतान केवल वैध मध्यस्थों को ही किए जाएं। SEBI का यह प्रस्ताव इस समय आया है जब पंजीकृत न होने वाली संस्थाएं निवेशकों को धोखा देकर अवैध रूप से धन इकट्ठा कर रही हैं। [\(Click here to read article\)](#)

BANK
MAHAPACK

for all Bank & Insurance
Exams

Selection Ka Saathi

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने रिपोर्ट किया है कि 31 दिसंबर 2024 तक ₹2000 मूल्यवर्ग के केवल ₹6,691 करोड़ के बैंकनोट प्रचलन में बचे हैं, जो 19 मई 2023 को इसकी वापसी की घोषणा के समय प्रचलित ₹3.56 लाख करोड़ का मात्र 1.88% है। इसका अर्थ है कि 98.12% उच्च-मूल्य के ये नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं। [\(Click here to read article\)](#)
- भारतीय ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पार्टनरशिप फॉर कार्बन एकाउंटिंग फाइनेंशियल्स (PCAF) के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह कदम बैंक की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें वह अपनी वित्तपोषित गतिविधियों से संबंधित ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को मापने और खुलासा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल के साथ, IOB न केवल वित्तीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अपने को संरेखित कर रहा है, बल्कि भारत के नेट-जीरो भविष्य की ओर यात्रा में अपनी भूमिका को भी मजबूत कर रहा है। [\(Click here to read article\)](#)
- दक्षिण भारतीय बैंक (SIB) ने भारत में तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बैंक ने दो विशिष्ट स्टार्टअप करंट अकाउंट उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें SIB बिजनेस स्टार्टअप करंट अकाउंट और SIB कॉर्पोरेट स्टार्टअप करंट अकाउंट शामिल हैं। ये अकाउंट्स उद्यमियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और स्टार्टअप के लिए बैंकिंग को सरल बनाने में मदद करते हैं, ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। [\(Click here to read article\)](#)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपनी छठी और अंतिम त्रिमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करने जा रहा है। नई आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5 से 7 फरवरी तक निर्धारित की गई थी। यह नई गवर्नर संजय मल्होत्रा के कार्यकाल की पहली आरबीआई नीति होगी और 1 फरवरी को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 के बाद पहली आरबीआई एमपीसी बैठक भी होगी। [\(Click here to read article\)](#)
- जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) रेपो दर को कम करता है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे आम जनता को कई फायदे मिलते हैं। रेपो दर वह दर होती है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। इस दर में कटौती से बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, और वे इस लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकते हैं। [\(Click here to read article\)](#)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 5 से 7 फरवरी 2025 तक अपनी 53वीं बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता RBI के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने की। इस बैठक में डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव ने भाग लिया। [\(Click here to read article\)](#)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन नाम जारी करने की घोषणा की है। अब भारतीय बैंकों के लिए 'Bank.in' और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) के लिए 'Fin.in' डोमेन निर्धारित किया गया है। [\(Click here to read article\)](#)

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (Q3 FY25) में 84% की सालाना वृद्धि के साथ ₹16,891 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो बाजार की अपेक्षाओं से अधिक रहा। बैंक की शुद्ध व्याज आय (NII) 4% बढ़कर ₹41,446 करोड़ हो गई, जबकि कर्मचारियों के खर्च में 17% की गिरावट आई। [\(Click here to read article\)](#)
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने डीबी रियल्टी लिमिटेड (अब वेलोर एस्टेट लिमिटेड) और सात संबंधित व्यक्तियों पर वित्तीय गड़बड़ियों और अनिवार्य खुलासों में चूक के लिए कुल ₹25 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा लेखा मानकों के उल्लंघन और पुणे बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (PBPL) के लिए बैंक ऑफ इंडिया को दी गई कॉर्पोरेट गारंटी को ठीक से उजागर न करने के कारण की गई। [\(Click here to read article\)](#)

Defence News

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 1 फरवरी 2025 को ओडिशा तट के चांदीपुर परीक्षण रेंज से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) के तीन लगातार सफल उड़ान परीक्षण किए। इन परीक्षणों को कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ने वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया गया, जिससे भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिली। इन ट्रायल्स ने मिसाइल प्रणाली की सटीकता, विश्वसनीयता और हवाई खतरों, विशेष रूप से ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिसंस को बेअसर करने की क्षमता को प्रदर्शित किया। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत के रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण क्षेत्रों को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि आईआईटी हैदराबाद में स्थित डीआरडीओ-इंडस्ट्री-अकादमिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DIA-CoE) ने लार्ज एरिया एडिटिव मैनुफैक्चरिंग (LAAM) सिस्टम विकसित किया है। यह नवाचार आईआईटी हैदराबाद, डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL) और विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से तैयार किया गया है, जो बड़े पैमाने पर धातु घटकों के निर्माण की प्रक्रिया को बदलने के लिए तैयार है। विशेष रूप से एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में, यह तकनीक भारत को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगी। [\(Click here to read article\)](#)
- TROPEX-25 (थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025) भारत द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों में से एक है, जिसमें भारतीय नौसेना की केंद्रीय भूमिका होती है। यह द्विवार्षिक अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों के समन्वय, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में शक्ति प्रदर्शन, और रणनीतिक तैयारियों को दर्शाता है। जनवरी 2025 में आयोजित TROPEX-25 भारत की विकसित होती सैन्य रणनीति और संयुक्त सैन्य अभियानों की क्षमता को दर्शाता है। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एकुवेरिन' (Ekuverin) का 13वां संस्करण 2-15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। यह द्विवार्षिक अभ्यास बारी-बारी से भारत और मालदीव में होता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उद्घाटन समारोह 2 फरवरी 2025 को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (MNDF) के आधिकारिक समग्र प्रशिक्षण केंद्र, माफीलाफुशी, मालदीव में आयोजित किया गया। [\(Click here to read article\)](#)

Awards and Recognitions

- भारतीय-अमेरिकी संगीतकार और व्यवसायिक नेता चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम 'त्रिवेणी' के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता। उन्होंने यह पुरस्कार 'बेस्ट न्यू एज, एंबिएंट, या चैंट एल्बम' श्रेणी में दक्षिण अफ्रीकी बांसुरीवादक वाउटर केलरमैन और जापानी-अमेरिकी सेलो वादक एरू मात्सुमोटो के साथ सहयोग में जीता। यह प्रतिष्ठित सम्मान 2 फरवरी 2025 को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में क्रिप्टो.कॉम एरिना, लॉस एंजेलिस में प्रदान किया गया। ([Click here to read article](#))

Summits and Conferences News

- अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) को आधिकारिक रूप से एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका मुख्यालय भारत में है। यह गठबंधन दुनिया भर में सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों—बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा—के संरक्षण पर केंद्रित है। साथ ही, यह अवैध वन्यजीव व्यापार, शिकार और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। ([Click here to read article](#))
- दुबई 12-13 अप्रैल, 2025 को दुबई प्रदर्शनी केंद्र में वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आई एम पीसकीपर मूवमेंट द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 2,800 शांति रक्षक और 72 वक्ता शामिल होंगे, जिनमें 10 नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान के संरक्षण में, यह कार्यक्रम यूएई के सामुदायिक वर्ष की पहल के साथ संरेखित है और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर न्याय, प्रेम और शांति को बढ़ावा देना है। ([Click here to read article](#))
- विम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025, 7 से 11 फरवरी 2025 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विम्सटेक देशों के युवा नेता एक साथ आएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच संबंधों को मजबूत करना है। युवा नेतृत्व वाली पहल, नेतृत्व और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर केंद्रित इस शिखर सम्मेलन का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ([Click here to read article](#))

Ranks and Reports

- भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर (PLF) में वैश्विक नेता बनकर उभरा है, जिसने 2024 में 86.4% का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया। इसने अमेरिका (84.1%) और चीन (83.2%) को पीछे छोड़ दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और दक्षता को दर्शाता है। 2024 में भारत के उड्डयन क्षेत्र ने 16.3 करोड़ घरेलू यात्रियों को सेवा दी, जो इसकी तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। ([Click here to read article](#))
- एक नए अध्ययन से पता चला है कि चल रहे जलवायु परिवर्तन का पश्चिम और मध्य अफ्रीका में कोको उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह क्षेत्र विश्व के 70% से अधिक कोको आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया और कैमरून में किए गए इस शोध के अनुसार, 2050 तक वर्तमान में उपयुक्त कोको उगाने वाले क्षेत्रों का लगभग 50% हिस्सा बढ़ते तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न के कारण खेती के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि कोको उत्पादन को बनाए रखने और वनों की कटाई को रोकने के लिए अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है। ([Click here to read article](#))
- भारतीय क्विक कॉमर्स स्टार्टअप Zepto ने वैश्विक स्तर पर फूड और ड्रिंक्स कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। Sensor Tower की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, Zepto ने KFC और Domino's जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है, जबकि McDonald's पहले स्थान पर रहा। यह उपलब्धि भारत के तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेक्टर को दर्शाती है, जहां Blinkit, Zomato और Swiggy भी शीर्ष 10 में शामिल हैं। Zepto की सफलता का श्रेय 2024 की दूसरी छमाही में 300% ग्रोथ और "बाय नाउ, पे लेटर" फीचर को जाता है। ([Click here to read article](#))

Sports News

- भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए मलेशिया के बायूएमास ओवल, कुआलालंपुर में खेले गए आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह भारत का इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरा खिताब है, जिससे भारतीय युवा महिला क्रिकेट टीम ने अपनी वैश्विक प्रभुत्वता को और मजबूत किया। ([Click here to read article](#))
- आर प्रज्ञानानंद ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड्स में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने रोमांचक टाई-ब्रेकर में डी. गुकेश को 2-1 से हराते हुए पहली बार टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब जीता। इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में कई अप्रत्याशित मोड़ आए, जिससे दर्शक अपनी सीटों के किनारे पर बैठे रहे। प्रज्ञानानंद की यह जीत उनके युवा करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जिसमें साथी भारतीय अर्जुन एरीगैसी की गुकेश पर शुरुआती जीत का भी बड़ा योगदान रहा। ([Click here to read article](#))

BANK

MAHAPACK PLUS

For IBPS, SBI, SIDBI, RBI
Grade B, +5 More

Selection Ka Saathi

Science and Technology News

- पूर्व विश्व नंबर 1 और दो बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने 33 वर्ष की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। रोमानियाई स्टार ने डोपिंग निलंबन के बाद चोटों से जूझते हुए वापसी की कोशिश की, लेकिन अंततः संन्यास लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने देश में आयोजित ट्रांसिल्वेनिया ओपन के पहले दौर में लूसिया ब्रोंज़ेट्टी के खिलाफ हार के बाद यह घोषणा की। हालेप के करियर की प्रमुख उपलब्धियों में विंबलडन 2019 और फ्रेंच ओपन 2018 खिताब शामिल हैं। उन्होंने अपने करियर में 24 WTA एकल खिताब जीते और \$40 मिलियन से अधिक की पुरस्कार राशि अर्जित की। [\(Click here to read article\)](#)
- पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 40 वर्षीय साहा, जो अपनी असाधारण विकेटकीपिंग और धैर्यशील बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने रणजी ट्रॉफी एलीट 2024-25 ग्रुप सी मुकाबले में बंगाल बनाम पंजाब मैच के दौरान अपना आखिरी मैच खेला। साहा ने इससे पहले नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। उन्होंने अपने परिवार, कोचों और क्रिकेट संगठनों का पूरे करियर में समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया। [\(Click here to read article\)](#)
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का थीम सॉन्ग 'जीतो बाज़ी खेल के' लॉन्च कर दिया है। यह गीत प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक अतिफ असलम द्वारा गाया गया है और टूर्नामेंट के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए जारी किया गया है। प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत होने में अब केवल 12 दिन शेष हैं। [\(Click here to read article\)](#)
- ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिंस ने वनडे क्रिकेट से तत्काल संन्यास लेने की घोषणा की, जिससे वह 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे। 35 वर्षीय स्टोइनिंस अब केवल टी20 क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इस प्रारूप में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। [\(Click here to read article\)](#)

Schemes and Committees News

- केंद्र सरकार ने कृषि प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादकता, सततता और किसानों की आय में सुधार करना है। ये पहलकदमियां डिजिटल प्रौद्योगिकियों, आधुनिक कृषि तकनीकों और संसाधन प्रबंधन की दक्षता को शामिल करती हैं, ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके और पर्यावरणीय सततता को सुनिश्चित किया जा सके। [\(Click here to read article\)](#)
- भारत में लिंग असमानता और घटते बाल लिंगानुपात को सुधारने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना शुरू की गई थी। इस योजना के उद्देश्यों को साकार करने के लिए ओडिशा सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जो किशोरियों को सशक्त बनाने, बाल विवाह रोकने और शिक्षा एवं आत्मरक्षा कौशल को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। ये पहल विभिन्न जिलों में लागू की गई हैं और इनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण तैयार किया जा सके। [\(Click here to read article\)](#)

- अपनी 8वीं संघीय बजट प्रस्तुति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के एकीकरण के लिए कैबिनेट की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और शासन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार ने AI से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन में पिछले वर्षों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। [\(Click here to read article\)](#)
- जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) ने सफलतापूर्वक पाँचवें H-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया, जो मिचिबिकी नंबर 6 उपग्रह को लेकर गया। यह उपग्रह जापान की पोर्जिनिंग प्रणाली में योगदान देगा, जो अमेरिका की ग्लोबल पोर्जिनिंग सिस्टम (GPS) का जापानी संस्करण है। यह प्रक्षेपण कागोशिमा प्रीफेक्चर के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:30 बजे हुआ, और उपग्रह को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। [\(Click here to read article\)](#)
- ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को बदल रही है, जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक सतत भविष्य की ओर बढ़ने का एक प्रभावी समाधान प्रदान कर रही है। पारंपरिक हाइड्रोजन उत्पादन विधियों के विपरीत, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती हैं और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती हैं, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जलविद्युत से उत्पन्न की जाती है। यह स्वच्छ ऊर्जा वाहक उद्योगों, परिवहन और ऊर्जा भंडारण को डीकार्बोनाइज़ करने की क्षमता रखता है, जिससे नेट-ज़ीरो उत्सर्जन के वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। [\(Click here to read article\)](#)
- इन्फ्लूएंजा, जिसे आमतौर पर फ्लू कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। यह हल्के से लेकर गंभीर रूप तक हो सकता है और कुछ मामलों में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के बढ़ने जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होता है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने से निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है। फ्लू का मौसम हर साल अलग हो सकता है, और इसके कारणों, लक्षणों, रोकथाम और उपचार को समझना सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए आवश्यक है। [Click here to read article\)](#)

Test Prime

ALL EXAMS,
ONE SUBSCRIPTION.

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपनी नवीनतम संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर "Finite Element Analysis of Structures (FEAST) 2025" का अनावरण किया है, जो 8वें राष्ट्रीय फिनाइट एलिमेंट डेवेलपर्स/FEAST उपयोगकर्ता मीट (NAFED08) के दौरान हैदराबाद स्थित IIT में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसमें 250 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने फिनाइट एलिमेंट-आधारित संरचनात्मक विश्लेषण में नवीनतम विकासों पर चर्चा की। ([Click here to read article](#))
- भारत ने बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) में देश की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों पर अनुसंधान को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के महानिदेशक और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. राजेश गोखले ने इस अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह नया शोध केंद्र टीकों और उपचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उभरते रोगों के लिए भारत की तैयारी को भी मजबूत करेगा। ([Click here to read article](#))
- ब्लू घोस्ट लैंडर एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है, जिसे फायरफ्लाई एयरोस्पेस (Firefly Aerospace) द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाना और चंद्र अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। यह लैंडर नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशंस प्रोग्राम (Lunar Surface Operations Program) और आर्टेमिस मिशन (Artemis Mission) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करना और वहां दीर्घकालिक खोज के लिए आधार तैयार करना है। ([Click here to read article](#))

Important Days News

- कैंसर आज मानवता के सामने सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और कई लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 2022 में कैंसर से लगभग 1 करोड़ मौतें हुईं। इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए, कैंसर मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, जो इस बीमारी से निपटने के लिए सभी स्तरों पर प्रयासों की आवश्यकता को दर्शाता है। ([Click here to read article](#))

- विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। ये पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता, मानव कल्याण और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में अहम योगदान देते हैं। 2025 की थीम 'हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा' है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत आजीविका के लिए आर्द्रभूमियों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देती है। ([Click here to read article](#))
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा 1-7 फरवरी तक मनाया जाने वाला विश्व अंतरधार्मिक सौहार्द सप्ताह (World Interfaith Harmony Week - WIHW) विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी समझ, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की एक वैश्विक पहल है। ([Click here to read article](#))

Obituaries News

- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नवीन चावला का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान उनके नेतृत्व और चुनावी सुधारों में उनके महत्वपूर्ण योगदान ने भारत की चुनावी प्रक्रिया पर गहरी छाप छोड़ी। एक अनुभवी सिविल सेवक के रूप में, उन्होंने चुनाव आयुक्त और बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कई अहम भूमिकाएँ निभाईं। उनके कार्यकाल को महत्वपूर्ण सुधारों और कुछ विवादों के लिए जाना जाता है। ([Click here to read article](#))
- लाखों इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता और प्रसिद्ध परोपकारी व्यक्ति आगा खान का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क (AKDN) के माध्यम से अपने वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए जाने जाने वाले, उन्होंने अपना जीवन विकासशील देशों में घरों, अस्पतालों और स्कूलों के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। उनका निधन इस्माइली समुदाय और दुनिया भर में परोपकार के लिए एक युग का अंत है। पुर्तगाल में अपने परिवार के साथ उनका निधन हो गया, उन्होंने एक आध्यात्मिक नेता, व्यवसायी और मानवतावादी के रूप में विरासत छोड़ी। ([Click here to read article](#))
- मैन अबाउट द हाउस और जॉर्ज एंड मिल्लेड में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर दिग्गज ब्रिटिश अभिनेता ब्रायन मर्फी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। प्यारे जॉर्ज रोपर की भूमिका निभाने के लिए मशहूर मर्फी का करियर दशकों तक चला, और उन्होंने 70 के दशक के सिटकॉम में एक स्थायी विरासत छोड़ी। आरएएफ में उनके शुरुआती अनुभवों और जोन लिटिलवुड के थिएटर वर्कशॉप ने उनके प्रतिष्ठित करियर को आकार दिया, जिससे ब्रिटिश टेलीविजन में एक प्रिय व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। ([Click here to read article](#))

Static Takeaways

Sr. No	Name	Static Details
1	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा मुख्यालय - मुंबई
2	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)	अध्यक्ष - माधवी बुच प्रधान कार्यालय - मुंबई
3	भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	सीएमडी - चल्ला श्रीनिवासलु प्रधान कार्यालय - मुंबई
4	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)	अध्यक्ष - नारायणन मुख्यालय - बेंगलुरु
5	JAXA (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी)	अध्यक्ष - हिरोशी यामाकावा

Sr. No	Name	Static Details
6	रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)	मुख्यालय - दिल्ली
7	ज़ेप्टो (Zepto)	सीईओ-आदित पालीचा
8	कोटक म्यूचुअल फंड	सीईओ - निलेश शाह मुख्यालय - मुंबई
9	उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक	सीईओ - संजीव नौटियाल प्रधान कार्यालय - बेंगलुरु
10	BIMSTEC	मुख्यालय - ढाका, बांग्लादेश
11	ओडिशा	राज्यपाल- हरि बाबू कंभमपति सीएम- मोहन माझी राजधानी-भुवनेश्वर
12	गुजरात	राज्यपाल- आचार्य देवव्रत सीएम-भूपेंद्र पटेल राजधानी- गांधीनगर
13	आंध्र प्रदेश	राज्यपाल- एस. अब्दुल नज़ीर सीएम- चंद्रबाबू नायडू राजधानी- अमरावती
14	केरल	राज्यपाल- राजेंद्र अर्लेकर सीएम- पिनाराई विजयन राजधानी- तिरुवनंतपुरम
15	राजस्थान	राज्यपाल- हरिभाऊ बागडे सीएम- भजन लाल शर्मा राजधानी- जयपुर
16	हिमाचल प्रदेश	राज्यपाल- शिव प्रताप शुक्ल सीएम- सुखविंदर सुक्वू राजधानी- शिमला
17	USA	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी - वाशिंगटन डी.सी.
18	पनामा	प्रमुख - जोस राउल मुलिनो राजधानी - पनामा सिटी
19	युगांडा	राष्ट्रपति - योवेरी मुसेवेनी राजधानी - कंपाला
20	न्यूजीलैंड	पीएम - माओरी राजधानी - वेलिंगटन
21	पाकिस्तान	पीएम- शहबाज शरीफ राजधानी - इस्लामाबाद
22	बेल्जियम	प्रधानमंत्री - बार्ट डी वेवर राजधानी - ब्रुसेल्स
23	रूस	राष्ट्रपति - व्लादिमीर पुतिन राजधानी - मास्को
24	दक्षिण अफ्रीका	राष्ट्रपति - सिरिल रामफोसा प्रशासनिक राजधानी - प्रिटोरिया
25	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	राष्ट्रपति - फेलिक्स त्सेसीकेदी राजधानी - किंशासा